

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on Strengthening of the working of the Ministry of DoNER for effective implementation of policies, programmes, schemes and projects meant for North Eastern Region.

**MOTION FOR ELECTION TO THE COURT OF
THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री [प्रो. (डा.) राम शंकर कथेरिया] : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ:-

“अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 की धारा 28 के निबंधनों के अनुसार इस अधिनियम के साथ संलग्न अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड (2) के साथ पठित खंड (1) की मद (xxiv) के अनुसरण में, यह सभा उस रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में श्री मोहम्मद अदीब और श्रीमती मोहसिना किदवई के कार्यकाल की समाप्ति और 9 नवम्बर, 2014 से श्री मुख्तार अब्बास नक़वी को केन्द्रीय मंत्री परिषद में शामिल किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों को उक्त कोर्ट का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।”

The question was put and the motion was adopted.

REGARDING OBJECTIONABLE REMARK BY A MEMBER

SHRI PRAMOD TIWARI (Uttar Pradesh): Sir, you have promised that you will allow me to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I first promised to Mr. Raja. ...*(Interruptions)*... Is it a point of order? ...*(Interruptions)*... I will call you also.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Supreme Court has ordered that Judges should not be referred to as “My Lord”. Why are you giving first opportunity to “Rajas”?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. I agree. ...*(Interruptions)*... That is a point to be considered. ...*(Interruptions)*... Zero Hour is Members’ hour. I have no problem. I will come to you. What is your point of order?